[Prof. P. J. Kurian]

World Health Organisation. The toxic effects of these chemicals on the biological syetem are too frightening to be described here.

Unfortunately, there is no satisfactory regulatory mechnism existing in this country. Therefore, in view of the serious health hazard being caused by the excessive use of pesticides, I would request the Government to take immediate steps to effectively regulate the use of toxic agro-chemicals in the country.

(iii) Demand for a Railway line between Sahajawan and Dorighat.

श्री महावीर प्रसाद (बांसगांव) : मान्यवर, मैं आपका ध्यान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसगांव जो शदियों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, में रेलवे लाइन के निर्माण के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन्, यह क्षेत्र सामाजिक आर्थिक एंव शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग नहीं है। मैं यदि औद्योगिकरण के प्रति राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं तो उत्तर में यही मिलता है कि उस क्षेत्र में रेलवे लाइन नहीं है। इस सार्वजनिक निजी, सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्रों में कोई भी उद्योग नहीं लग सकता है। यही नहीं जहां तक मेरी जानकारी है कि भारत वर्ष में एक मात्र तहसील बांसगांव है जहां पर एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं है। इससे बढ़कर मेरे लिए तथा उस क्षेत्र की जनता के लिए दूर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। इस संबन्ध में मैंने कई बार इस सदन में आवाज उठाई है लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं सहजनवां से दोहरीघाट तक रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में तीन-तीन बार सर्वेक्षण हो चुका है तथा संकेत पत्थर भी लग चुके हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद कहा जा रहा है कि दस प्रतिशत आर्थिक प्रतिफल नहीं आ रहा है इसलिए इस योजना पर विचार करना अभी संभव नहीं है। अत: आपके माध्यम से पुन: निवेदन है कि मई सन् 1980 की जो राष्ट्रीय परिवहन नीति बनी है उसको आधार मानते हुए तथा आर्थिक प्रतिफल को त्यागते हुए क्षेत्रीय पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सयजनवां से दोहरीघाट तक रेलवे लाइन बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए ताकि मेरी तहसील की जानता भी रेलवे लाइन का दर्शन कर सके।

(iv) Staff transfer Police in I.O.C

SHRI BHEEKHABHAI (Banswara) : It is a matter of great surprise that though the Refineries Division of Indian Oil Corporation was established in October 1958, i.e. over a quarter of century ago, they have not yet framed any regular and clear cut transfer policy. The transfers were carlier effected mostly for Technical Officers, when the actual needs were felt. But, for the last three to four years the transfers in Refineries Division are being effected in a big way though each transfer costs the Management Rs. 10,000 to Rs. 20,000 due to its liberal transfer policy.

Another paradoxical situation is that though the staff members/workmen are also liable to transferred to other units, they are never moved from one station to other station. It is suggested that to avoid harassment and hardships, the following action be taken :—

I. No movement of officers should take place till a broad, enlightened and clear transfer policy is framed by the Corporation in consulation with recognised Unions and Officers' Association.

II. Transfers should be minimum as each transfer costs several thousands of rupees.

III. Each officer should be informed of the proposed transfer at least one year in advance.

VI. If both the spouses are serving either in I.O.C. or outside I.O.C., they need not be dislocated as far as possible or both should work at the same station/unit.

(v) Need for probe into allegation of Supply of pelluted water to the people of Agra

श्री निहाल सिंह जैन (आगरा) : सभापति महोदय, में आगरा में थल सेना एवं वायु सेना की बहत बड़ी छावनी स्थिति है । यहां पैराशू ट्रेनिंग का एकमात्र प्रशिक्षण केन्द्र है । यहां सी.ओ.डी., 509 अर्मी बेस वर्क शाप, एवं अन्य रक्षा प्रतिष्ठान हैं । बहुत बड़ी संख्या में थल सेना, वायु सेना के जवान, अधिकारी एवं इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी निवास करते हैं । इन सबकों पेयजल की आपूर्ति आगरा जल संस्थान करता है । कैमीकल परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि जल संस्थान द्वारा वितरित पेयजल अत्यन्त दूषित है तथा सामान्यत: अस्वास्थ्यकर है। विशेषज्ञों का मत है कि यह दूषित जल अस्सी प्रतिशत रोगों को जन्म दे रहा है इसके परिणाम: स्वरूप हमारे सुरक्षा सैनिक अधिकारी तथा रक्षा प्रतिष्ठानों के अधिकारी भी अछूतें नहीं रह सकते । चिन्तनीय स्थिति तो यह है कि उत्तर प्रदेश शासन और जल संस्थान विशुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में उपेक्षा कर रहे हैं । जल में विषाक्त कीटाणु और गन्दगी की शिकायतें अनवरत रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं नगर में महामारी न फैल जाए ?

उपरोक्त सैनिक प्रतिष्ठानों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नगरवासियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञ तुरन्त आगरा भेजे जाएं जो जल सस्थान से प्राप्त होने वाले जल की रासायनिक जांच और उसको प्रदूषण रहित बनाने की प्रक्रिया का भी अवलोकन करें और यह भी सुनिश्चित करें कि सुरक्षा सेवा कर्मचारियों को पेयजल प्रदूषण रहित उपलब्ध हो ।

(vi) Strike be Hoisery Industry workers of Tiruppur in Tamilnadu and West Bengal

SHRI ERA MOHAN (Combatore) : Triuppur in Tamil Nadu is the home of hosiery industry in India with 1,300 factories employing 16,00 workers. The vests made in Tiruppur are supplied throughout the country and outside India, even to advanced countries. For the past one week all these units have been closed after negotiations have failed. The 16,000 workers are on the roads. There is the chain reaction of stagnation of yarn and the spinnin mills are laying off workers. For the past three months the hosiery industry in West Bengal is also on strike. The Centre should make serious efforts to resolve this strike. The export commitment is not being adhered to in the absence of continued production. It is very necessary to find a solution to the genuine demands of the hosiery industry workers for wage increase and other basic amenties. The Centre should intervene immediately and ensure early settlement of strike in hosiery industry in Tiruppur and West Bengal, so that thousands of workers are saved from decimation.